तलाशियों के परिणामस्वरूप प्रथम-दृष्टया 110.76 लाख रु० के मूल्य की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थीं। उपर्युक्त तलाशियों के दौरान जिन व्यक्तियों की तलाशी ली गई थी, उन्होंने कुल 550.37 लाख रु० की आय को छिपाने की बात को स्वीकार कर लिया है।

(ग) किसी व्यक्ति को भी गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि तलाशियों के दौरान गिरफ्तारी के लिए आयकर अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है।

(घ) प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के तहत सभी मामलों में उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

Violation of Norms of RBI and NABARD by Various States

190. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the names of the States which have violated the guidelines and norms of the Reserve Bank of India and NABARD regarding interest on loans to farmers and rescheduling of these loans; and

(b) what steps the Central Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) It was noticed by Reserve Bank of India (RBI) and National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) that some cooperative banks were not fully complying with instructions relating to interest rates, conversion of loans etc. and directives in this regard were violated in 12 States and one Union Territory namely: (1) Andhra Pradesh, (2) Bihar, (3) Gujarat, (4) Haryana, (5) Karnataka, (6) Kerala, (7) Madhya Pradesh, (8) Maharashtra, (9) Orissa, (10) Punjab (11) Tamil Nadu, (12) West Bengal and (13) Union Territory of Pondicherry.

(b) NABARD *vide* its circular dated 29th November, 1988 addressed to the Managing Directors of all State Cooperative Banks and State Land Development Banks, withheld refinance facilities till an undertaking is furnished by the concerned institutions that they would follow the instructions/guidelines issued by the RBI/NABARD.

NABARD has reported that refinance facilities have been resumed in all States, except in Maharashtra, Madhya Pradesh and Pondicherry, since undertakings from the apex banks of these States/Union Territories are still awaited.

दिल्ली में मतदाता सूचियों में संशोधन किया जाना

191. **श्री संतोष बागड़ोदिया:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चुनाव आयोग ने संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली के सभी चुनाव-क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में संशोधन करने के आदेश दे दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मतदाता सूचियों के संशोधन सम्बन्धी कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) दिल्ली में 18 वर्ष की आयु के अनुमानत: कितने युवक-युवतियां मताधिकार प्राप्त कर सकेंगे?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) जी, हां।